IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उत्तर बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के उन्नति में नाबार्ड की योगदान

डॉ0 संजीव कुमार प्रभाकर (वाणिज्य)
पिता– महेश प्रसाद
ग्राम– बुन्देलखण्ड
पो0 बासोपट्टी
जिला– मधुबनी (बिहार)

नाबार्ड (NABARD) अर्थात इनका विस्तृत रूप National Bank for Agriculture and rural Devolopment राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के उन्नति हेतू वित्त उपलब्ध कराने वाली एक शीर्ष संस्था है गाँव के एकीकृत उन्नति के इरादे से सांसद अधिनियम 1981 के आधार पर 12 जूलाई 1982 को शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक से कुछ कार्य अलग कर इसकी स्थापना की गई जिस समय इसकी स्थापना हुई उसकी प्रदत पूँजी 100 करोड़ रूपये थी जो वर्त्तमान में 5000 करोड़ तक पहूँच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाले इस बैंक का लक्ष्य प्रभावी ऋण समर्थन, संबंधित सेवाओं संस्थागत विकास और अन्य नवाचारी प्रयासों के जरिये ग्रामीण क्षेत्र के उन्नति का संवर्धन करना है। इसके माध्यम से उत्तर बिहार के अन्तर्गत आनेवाले जिलो यथा–दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, आदि के ग्रामीण क्षेत्रो के अध्ययन करने का प्रयास किया गया है एवं उक्त जिलो में नाबार्ड द्वारा किये गए कार्यो का भी विश्लेषण किया गया। इसके अंतर्गत उत्तर बिहार के अंतर्गत आने वाले जिलो में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के उन्नति में दिये गए वित्तीय सहायता का भी उन्मूलन किया गया है।

जैसे कि हम सभी जानते है। कि यह भारत का एक ऐसा वित्तीय संस्था है जो आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण क्षेत्र के उन्नति के लिए शहरी क्षेत्रों से भी धन जुटाता है जहाँ तक इसके क्षेत्र दायरा कि बात है तो प्रत्येक राज्य के राजधानी एवं देश के लगभग 400 छोटे–बड़े जिलो में इसकी क्षेत्रीय कार्यालय है जिसमें लगभग 3000 अधिकारियों एवं 1800 कर्मचारी कार्यरत है एवं इनका मख्यालय मुम्बई में है इनके 6 प्रशिक्षण संस्थान भी है। यह गाँव के किसानों को ऋण, बेरोजगारों को रोजगार का अवसरों पैदा कर एवं महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एवं विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को उन्नति के लिए प्रयासरत है।

ग्रामीण क्षेत्र के उन्नति के लिए नाबार्ड बैंको, सहकारी ऋण संस्थाओं और राज्य सरकारों के लिए चार प्रकार के ऋण प्रदान करता है।

1. लघु अवधि ऋण (18माह)–

नाबार्ड किसानों के लिए विभिन्न फसलों एवं मौसमी कृषि, मछली पालन, वानिकी, हथकरधा बुनकरो आदि के लिए वित्तीय सहायता के अनुसार रियासती ऋण उपलब्ध करता है (वर्ष 2009–10 में लगभग 24,000 करोड़ रूपयों)

2. मध्यमावधि ऋण (3 वर्ष से 7 वर्ष तक)

इसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ, सुखाड़, ओलाविस्ट, बज्रपात आदि के कारण होने वाले कृषि हानि के लिए परिवर्तनीय ऋण।

3. निवेश ऋण (3 वर्ष से आगे 25 वर्ष तक)

इसके अंतर्गत पूँजी निर्माण के वास्ते ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। एवं किसानो के आय में वृद्धि एवं उत्पादन एवं उत्पादकता क्षमता में तकनीकी उन्नयन के लिए भी सहायता दी जाती है।

(वर्ष 2009–10 में 11984 करोड़ रूपयें)

4. ग्रामीण बुनियादी संरचना कोषः–

बुनियादी संरचना आकार में वृद्धि एवं ग्रामीण ऋण में सरकारी बजट अपर्याप्त होते है इसलिए 5 वर्षो के लिए सावधि ऋण रियायती दरो पर दिये जाते है यह ऋण यह वाणिज्यक बैंक के माध्यम से दिये जाते है सामान्यतः इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 31 प्रमुख क्षेत्रो को इस योजना के माध्यम से ऋण दिये जाते है। इसमें 45% सड़को के विकास 45% ग्रामीण क्षत्रों के सिंचाई के लिए एवं 10% सामाजिक क्षेत्र के उन्नति के लिए दिये जाते है इसके अतिरिक्त विगत कुछ वर्षो में नाबार्ड ने ग्रामीण ग्राहको, सामाजिक–आर्थिक अधोसंरचना का सुदृढीकरण, प्रभावी और किफायती ऋण योजनाएँ एवं सेवाऐं ग्रामीण मूल्य–श्रृखला, प्रसार सेवाआ का विस्तार आदि को सुदृढ एवं सुलभ बनाने में योगदान दिया है ताकि ग्रामीणा क्षेत्रो का उन्नति हो सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नति के लिए नवाचार, अनुप्रयोग, मार्गदर्शक और उत्पादो एवं सेवाओ का स्तर ऊँचा उटाने के लिए नाबार्ड अपनी ओर से सराहनीय पहल करता रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नति के लिए नाबार्ड निम्न–लिखित कार्य कर सराहनीय योगदान दे रहे है जो निम्न–लिखित है।

ग्रामीण रोजगार के जरिये गरीबी उन्मूलनः–

- रोजगार सृजन हेतू आर0ई0डी0पी0 / आर0यू0डी0एन0ई0टी0आई0एस0।
- स्वयं सहायता समूह हेतू सूक्ष्म उद्यम।
- स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का उत्थान।
- स्वयं सहायता समूह हेतू विपणन का अवसर।
- निवेश ऋण में वृद्धि हेतू नवाचारी कृषि पद्धतियो।
- कृषि हेतू पूँजी जुटाने हेतू बैचर कैपिटल फंड (राज्य क्रेडिट)
- बाँस और बैंक विकास
- किसानो द्वारा मिनी कृषि प्रसंस्करण उद्यमो हेतू उप्पादको की कंपनिया।

❖ **ग्रामीण अधोसंरचनाः–**

- ई–गवर्नेस और ई–मेल सुविधाओं के माध्यम से आई सी टी का उपयोग।
- स्वयं सहायता समूह हेतू कृषि, पोर्टल, प्रशिक्षण एवं अभिलेखा का रख–रखाव।
- व्यापक पंचवर्षीय योजना।
- कृषि हेतू पंचवर्षीय जिला योजना।
- ग्राम पंचायतो के माध्यम से ग्रामीण हाटो का निर्माण।
- ग्रामीण स्तर पर अक्षय प्रणाली, बायोगैस, बायोडिजल, सौर उर्जा, पवनउर्जा एवं पनबिजली प्रणाली आदि की अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- पेयजल, स्वच्छता आदि योजनाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

❖ **ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगः–**

- ग्रामीण महिलाओं द्वारा उत्पादित गैर–कृषि उत्पादो के लिए ऋण सहायता प्रोत्साहित करना।
- कृषि प्रसंस्करण पर जोर देना।
- ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता से संबंधित कौशल को विकसित कर उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- ग्रामीण रोजगार सृजन

❖ **संस्थागत वैकासिक प्रयासः–**

- ग्रामीण क्षेत्रो में ऋण को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल में (संभावनायुक्त योजना) के जरिये जिला ऋण योजना।
- कृषि परियोजना का मूल्यांकन करना।
- जिला निगरानी अध्ययन
- बैंक के कार्मिको का प्रशिक्षण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त संबंधी जोखिमों को कम करने हेतू TME प्रकोष्ठ।
- नैबकांस आदि के मूल्यांकन हेतू परामर्श शाखा

ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नति के लिए उदार ऋणों के रूप में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के उदेश्य से नाबार्ड ने अनेक प्रकार के उदेश्य केन्द्रित कोष को स्थापित किए है ताकि समय–समय पर इस कोषों के माध्यम से गाँव के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष ऋण प्रवाह हो सके।

यह अपनी ऋण संबंधी जरूरतों की पूर्ती भारत सरकार, विश्व बैंक एवं अन्य ऐजेंसियों से राशि प्राप्त करता है। एवं फिर इस राशि को ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक गतिविधि को बढावा देने के लिए राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यक बैंक एवं क्षेत्रीय बैंक के माध्यम से पुनर्वित सुविधाऐं प्रदान करता है।

1 अप्रेल 1995 से नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गइ। हाल के दिनो में भारत के बैंकिग क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए है एवं जिसका प्रभाव यह है कि बैंको के परिसंपति, गुणबता और लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ है। आज ग्रामीण क्षेत्र के उन्नति म बैंक का महत्वपूर्ण योगदान हैं। भारत में RIDF बजट के दौरान वार्षिक रूप से घोषित की जानेवाली धन–राशि के साथ वर्षानुवर्ष जारी रहा है 2007–08 तक 13 श्रृंखलाऐ पुरी की जा चुकी है। इस प्रकार RIDF-1 से RIDF-xiii तक कुल कॉर्पस 72,000 करोड़ रूपये हो गया है। RIDF तहत 11 जनवरी 2008 तक स्वीकृत तथा वितरित ऋण की राशि क्रमशः 69,883 करोड़ तथा 41,360 करोड़ रूपयें नही थी वर्ष 2007–08 के बजट प्रस्तावो में RIDF के लिए 12,000 करोड़ रूपय का प्रवधान किया गया था वर्ष 209–10 के अंतिम बजट में RIDF-XV के तहत 14,000 करोड़ रूपयें आवंटित की गई है। 31 दिसम्बर 2007 तक RIDF (i से vii) की पहली सात ट्रांशो को बंद कर दिया गया है और RIDF VII से X तक ट्रांशो के अतंर्गत चलने वाली परियोजना की अवधि 31 मार्च 2008 तक बढा दिया गया है IRDF-xi तथा XII को बंद करने की निर्धारित तिथियों क्रमशः 31 मार्च 2008 तथा मार्च 2009 है वर्ष 2008–09 के दौरान इस संस्था ने 54248.5 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किए तथा 50029.6 करोड़ रूपयें के ऋण वितरित किए।

बैंकिग क्षेत्र में अमूलचूक सकारात्मक परिवर्तन हुए वर्ष 2001 से बैंकिग सूचकांक 51% वार्षिक दर से बढ रहा है जबकि बाजार विकास सूचकांक इस अवधि में 27% तक सीमित रहा। सभी अनुसूचित वाणिज्यक बैंक के लिए पूँजी के मुकाबले में जोखिमयुक्त परिसंपतियों का अनुपात 2001 के 11.4% से बढकर अब 13.2% हो गया जो नेशनल फ्रेमवर्म क तहत निर्धारित 8% से भी अधिक है यह R.B.I के लिए अपनाये गये 9% से भी अधिक है।

वर्त्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों के उन्नति में कुछ विकराल चनौतियाँ यथा खाद्या सुरक्षा की सतत् माँग, वित्तीय समावेशन की आवश्यकता गरीबी उन्मूलन की चुनौती, ग्रामीण ऋण प्रवाह में विस्तार ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का सुदृढीकरण, ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना, युवाओं को नियमित कौशल प्रशिक्षण, एवं स्वयं सहायता समूह का विकास आदि।

नाबार्ड सामान रूप से इन सभी कार्यो पर मुस्तैदी से जुटा हुआ है। एवं इस दिशा में सार्थक समर्थ भी हो रहा है।

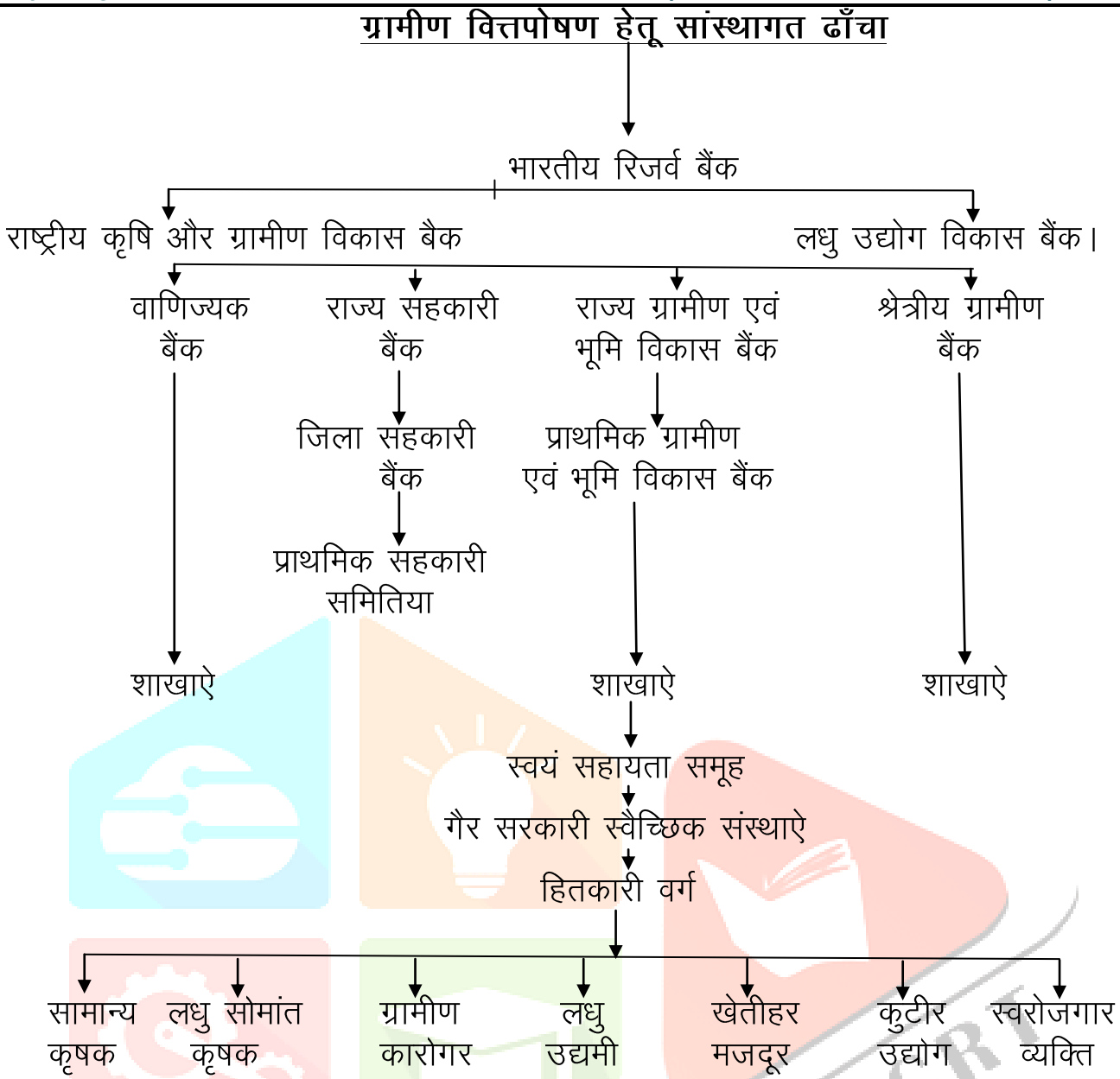

नाबार्ड मुख्यतया तीन तरह के कार्य करते है। वित्तीय विकासात्मक और पर्यवेक्षी। वर्ष 2019–20 के दौरान नावार्ड ने सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को मौसमी कृषि परिचालनो के लिए 92411 करोड़ और मौसमी कृषि परिचलनो से इतर 7971 करोड़ की राशि संवितरित की है साथ ही दीर्धावधि पुनर्वित के तक वर्ष 2019–20 में 78180 करोड़ की राशि वितरित की है। ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास नीधि के तहत नाबार्ड ने वर्ष 2019–20 के दौरान 26,266 करोड़ की राशि संवितरित की है दीर्धावधि सिचाई निधि 31 मार्च 2020 कि स्थिति में LTIE के तहत संचयी मंजूरियो की राशि 81865 करोड़ एवं संचयी संवितरणों की राशि 44719 करोड़ थी। सूक्ष्म सिंचाई निधि के तहत वर्ष 2019–20 से नाबार्ड में 5000 करोड़ के नीधि की व्यवस्था की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान नीडा के तहत 11 ऋण प्रस्तावों के माध्यम से 4382 करोड़ सावधि ऋण की मंजूरी दी गई जिसका 78% हिस्सा सिचाई परियोजना के लिए तथा शेष हिस्सा विद्युत संचार तथा वाटरसड परियोजनाओ (41 करोड़) के लिए था।

नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्र के उन्नति के लिए अवतक 154 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ 34,878 कार्यक्रम के जरीए 2.04 लाख ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण हेतु रोजगार उपलब्ध कराया है। वर्ष 2019 के दौरान नाबार्ड ने 19 करोड़ अनुदान सहायता के साथ 1066 कौशल विकास कार्यक्रम के जरिए 33,216 लाख ग्रामीण युवाओं का कौशल विकास किया।

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 62 ग्रामीण हाटो को 6 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की कई।

नाबार्ड ने सहकारी बैंक हेतू शुरू की गई बिहार में कुल 23 बैंको की 310 शाखाओं में सी बी एस (CBS) परियोजना शुरू की है।

नाबार्ड ने बैंको और वित्तीय संस्थानो के लिए 5000 करोड़ रूपयें की पुनर्वित याजना का ऐलान किया है 2150 वाटरसेड विकास परियोजिना के लाभाथियो को वित सहायता प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2020–21 में 5000 PACS, 2021–22 में 15000 PACS एव वित्तीय वर्ष 2022–13 में 15000 PACS को अपग्रेड करने की योजना बनाई है।

निष्कर्षः–

उपरोक्त सभी पहलूओं के अध्ययन के उपरांत कहा जा सकता है कि नाबार्ड एक शीर्ष वित्त बैंक है। जो आवश्यकता पड़ने पर कृषिक एवं ग्रामीणों को उत्पादक तथा अनुत्पादक उदेश्य के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्धकालीन ऋण की पूर्ती करती है। एवं विभिन्न संस्थाओं को पुनर्वित सहायता प्रदान करती है साथ ही अनुवीक्षण एवं पयवेक्षीय कार्य भी करती है। जहाँ तक उत्तर बिहार के विभिन्न जिला यथा दरभंगा मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, एवं सुपौल जिल के ग्रामीण क्षेत्रों के चौमुखी उन्नति में योगदान की बात है तो इसमें यह अपनी सर्वश्रेष्ठ कर्त्तव्य का पालन कर रही नाबार्ड ने इन क्षेत्रों के उन्नति के लिए किसान, वेरोजगार,उद्यमी, स्वयं सहायता समूहो एवं बैंको जैसे संस्धानो को भी नवाचार के माध्यम से अनेक सुविधा प्रदान कर रही हे। इसस उत्तर बिहार के ग्रामीण क्षेत्र उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर हो रहा है फ्लतः उत्तर बिहार की आर्थिक दशा सुदृढ हो रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ।

1. वार्षिक प्रतिवेदन नाबार्ड भारत सरकार
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2007–08 भारत सरकार नई दिल्ली
3. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया वार्षिक प्रतिवेदन
4. नाबार्ड का वेबसाइट
5. प्रसाद जगदीश (2000), नव बिहारः एक भविष्य निरूपण, तन्या प्रेस पटना।
6. Binswanger- Mkhize, Hans P. and Alwen D' Souza, 2011@ "India 1961-2010 Structure" Background paper to Centennial Gropes 2012"
7. Ahluwalia, Monte's 2001, Report of the Task Force on Employment opportunities, Planning commission, New Delhi,
8. आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 भारत सरकार
9. आर्थिक प्रतिवेदन बिहार सरकार
10. द्विवेदी रामेशचन्द्र (1992) ग्रामीण क्षेत्र के लिए सुविधा का विस्तार योजना, वर्ष–36 अंक 18, 15 नवम्बर, पृष्ट– 34